

(c) Does not arise

SHRI NAWAI KISHORI SHARMA  
I have only to thank the hon Minister instead of asking a question

MR SPFAKER I thank you for sitting down so early

रतगुवा नहर परियोजना (मध्य प्रदेश)  
के कार्य की प्रगति

\*556 श्री नाथूराम अहिरवार क्या सिंचाई और विद्युत मंत्रालय बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छतरपुर (मध्य प्रदेश) में रतगुवा नहर परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुका है और उसके लिए 290 करोड़ रुपए का धनगणित की मजूरी दे दी गई है और

(ख) यदि हा तो क्या इस परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बंजनाथ कुरोल) (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 186 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर रतगुवा परियोजना का प्रस्ताव किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच परियोजना के कुछ पहलुओं पर अभी भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री नाथूराम अहिरवार . मैं न चाहता हूँ कि इस केनाल योजना के लिए सरकार कितने दिन से विचार-विमर्श कर रही है ? अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पैसा मंजूर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कौन सी अडचन आ रही है जिसकी वजह से इस योजना को डिले किया जा रहा है ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR K L RAO) The dam was constructed some years ago by the

Uttar Pradesh Government in Madhya Pradesh area. The Madhya Pradesh Government has claimed now that they want to make use of some amount of water for irrigation. Naturally this has led to a discussion between the two State Governments. They have not yet come to an agreement so far. It is an old irrigation system. We are trying to sort it out. I am sure we will be able to find a way out. I will be having a discussion on this matter.

श्री नाथूराम अहिरवार . जब दोनो राज्य सरकारों एक दूसरे से सहमत नहीं है तब सिंचाई मंत्रालय स्वयं बैठ कर इस मसल का क्या जल्दी हल नहीं करत है। यह 67 मील लम्बी केनाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दम वात का वादा किया था जब मध्य प्रदेश की जमीन ली गई थी, कि हम पानी देंगे। जब बांध का कस्ट्रक्शन हो रहा है और हमारा यहाँ पानी की कमी है तो इस बात का ध्यान रखत हुए कि मध्य प्रदेश का ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या मंत्री महोदय पानी दिलवाने की गारंटी करेंगे और नहर को पूरी करायेंगे ?

DR K L RAO That is what I submitted. I will try to find a way out of this problem. I am sure we will be able to do that.

श्री फूल चन्द वर्मा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस योजना के सबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच में अन्तिम चर्चा कब हुई और उस चर्चा के दौरान कौन-कौन से मुद्दों पर बात-चीत की गई ?

DR K L RAO The Chief Engineers of the two States had a discussion with the Chairman of the Central water and power Commission to find a way out. But they were not able to do so. Then, the Uttar Pradesh Chief Engineer was to go there along with the Madhya Pradesh Chief Engineer to get some way out. But that was also not done. It is a small quantity in terms of water but it is very valuable because Madhya Pradesh has no irrigation. I quite appreciate it. I think, I will be able to find a way out, as I stated earlier, in one or two months time.

श्री अरविन्द नेताम : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस योजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

DR K L RAO In Uttar Pradesh, it is already irrigating an appreciable amount of land. In Madhya Pradesh I do not know the actual extent of land for irrigation, but, I think, it is about 20,000 acres in kharif and 17,000 acres in rabi.

MR SPEAKER Shri N N Pandey

श्री फूलचन्द वर्मा मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं। अभी वहाँ सिंचाई शुरू नहीं हुई है। उनको उस बात की सही जानकारी नहीं है।

DR K I RAO There is no canal. How can there be any irrigation? As I said I am trying to sort out the canal alignment. Where is the question of giving a wrong information?

SHRI NARSINGH NARAIN PANDY I want to know what are the impediments in the way which have not so far led to an agreement between the Chief Engineers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, sitting together and binding a way out?

DR K L RAO They have had a discussion and they have differed. I can understand the problem. The project had been done by the Uttar Pradesh Government and a good amount of land has been brought under irrigation. The Madhya Pradesh Government is now claiming it saying, 'It is in our area. Why don't you allow us to have some water and have irrigation?' The Uttar Pradesh Government says, 'It is an old irrigation system. Why are you interfering with it?' This has got to be sorted out.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश भूमि डम म गट है और उसका वारनबिक लाभ उत्तर प्रदेश सरकार उठाना चाहती है और मध्य प्रदेश को उसका चौथाई लाभ भी देना नहीं चाहती

है ? यदि यह सही है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मध्य प्रदेश का वह इलाका एक डाकू-ग्रस्त क्षेत्र है और उस इलाके को अधिक सिंचाई की सुविधाये प्राप्त होनी चाहिये, क्या आप इस बात की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लाभ मध्य प्रदेश को उमने मिले ?

DR K I RAO The entire dam-site is in Madhya Pradesh area. The hon Member was saying that it was a dacot-infested area and, therefore, irrigation must be extended. That is not so much an important reason. There is a more important reason and that is, being one of the largest States in India, Madhya Pradesh has got the least irrigation while it has got a high irrigation potential. It is in the interest of the country that we should see that this State is supplied with irrigation to a larger extent than what we are doing now.

श्री रामचन्द्र विकल जा याजना बनाई गई है उमने जा खर्चा हुआ है, उस खर्च में मध्य प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा है और उत्तर प्रदेश सरकार का कितना हिस्सा है और क्या उसी हिसाब में आप बटवारा करने जा रहे हैं या नहीं ?

DR K L RAO It is not a joint reservoir. The reservoir has been built by U P entirely. Now the question is whether M P should be allowed to construct a canal from the reservoir. If that is done, that will be done entirely at the cost of Madhya Pradesh. The dispute is not about money. The question is about allowance of water, how much water should be allowed to be used by Madhya Pradesh.

#### Rural Electrification in Gujarat

\*560 SHRI VEKARIA Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state

(a) whether the Rural Electrification Corporation has sanctioned any loan to rural electric supply cooperatives in Gujarat for 1971-72 and 1972-73, and